

गरीबी का अर्थ, दृष्टि; ; u (Poverty in India: A Study)

डॉ. अनूप कुमार गुप्ता*

प्रस्तावना

गरीबी का अर्थ; ; u (Meaning of Poverty)

गरीबी-सामान्य की शब्दावली में 'गरीबी' अथवा 'अवस्था' किसी व्यक्ति की उस अवस्था का द्योतक है जब उसके पास कोई धन-सम्पदा न हो और उसकी आय अत्यन्त कम हो अर्थात् व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने असमर्थ हो। भारत में गरीबी से आशय लोगों के निम्न जीवन निर्वाह स्तर से होता है। "विश्व विकास रिपोर्ट 1990"के अनुसार, "निर्धनता न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने की अक्षमता है।"

"गरीबी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी आय जुटाने में असमर्थ होता है अर्थात् ऐसे सभी व्यक्ति गरीब समझे जाते हैं जो खर्च का भार उठाने में असमर्थ हो एवं जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हों।"

गरीबी के प्रकार (Types of Poverty)

गरीबी की कोई-सर्वमान्य परिभाषा नहीं है जो पूरे विश्व में सबको स्वीकार्य हो। गरीबी की अवधारणा को निम्न दो रूपों में ज्ञात किया जा सकता है।

- गरीबी का निरपेक्ष स्तर (Absolute Level of Poverty)

निर्धनता की इस अवधारणा के अनुसार, निर्धन व्यक्ति वह जिसकी आय इतनी कम है कि वह न्यूनतम भरण-पोषण अर्थात् भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य आदि आधारभूत आवश्यकता को भी प्राप्त करने में असमर्थ है। विश्व बैंक के अनुसार, निरपेक्ष निर्धनता को रोटी की आवश्यकता की रेखा से नीचे की निर्धनता के रूप में वर्णित किया जाता है जिसका अर्थ है, उपभोग की जाने वाली कैलोरी तथा न्यूनतम उपभोग स्तर के द्वारा गरीबी का मापन करना। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री 'कुल्लु एच. डल' इसे 'गरीबी रेखा' कहते हैं। उनसे अनुसार निर्वाह हेतु संघर्ष जो मानव जाति के लिए अब तक प्राथमिक एवं ज्वलन्त समस्या रही है, के पक्ष में 'आर्थिक और स्थायी विकास' (economic and sustainable development) हमारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह उच्च जीवन-स्तर को प्राप्त करने का आवश्यक साधन है।

- गरीबी का सापेक्ष स्तर (Relative Level of Poverty)

यह स्तर आय की विषमता से सम्बद्ध है। यहाँ सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता (असमानता) है। सापेक्ष गरीबी दो देशों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना पर आधारित है। इस तुलना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश की तुलना में निर्धन है। अतः निर्वाह स्तर को आयकर उपभोग व्यय के रूप में मापा जाता है।

* एम.कॉम., पीएच.डी., बरेली, यू.पी.।

गरीबी को निरपेक्ष गरीबी सापेक्ष गरीबी में विभाजित करना उचित नहीं है। गरीबी वस्तुतः निरपेक्ष है, क्योंकि आय के वितरण की असमानता निरपेक्ष गरीबी नहीं है।

Estimates of Poverty

घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर निर्धनता के स्तर एवं सघनता का मापन अत्यधिक चुनौतीपूर्ण एवं विवादास्पद मुद्दा रहा है। अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों के स्तर पर अभी तक ऐसी कोई भी सर्वमान्य विधि अथवा फॉर्मूला अथवा उपागम विकसित नहीं किया जा सका है, जो देशकाल एवं परिस्थितियों के स्वरूप अधिक-से-अधिक सटीक तथा वृहत् स्तर पर स्वीकार्य हो। भारत का योजना आयोग समय-समय गरीबी अथवा गरीबी अनुपात का अनुमान लगाता है, जोकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office: (NSSO)) द्वारा किया जाता है। निर्धनता के आकलन पर सर्वाधिक आलोचनात्मक विवाद योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मार्च 2011 में दायर एक शपथ-पत्र को लेकर हुआ, जिसमें योजना आयोग ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ₹ 965 प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 781 प्रतिमाह से अधिक खर्च करने वाले लोग निर्धन नहीं हैं। आयोग ने यह भी कहा कि ₹ 32 प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 26 प्रतिदिन खर्च करने वाले लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए चलाई गई योजनाओं के अनतर्गत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। यह आकलन प्रो. एस.डी. तेन्दुलकर समिति द्वारा सुझाई गई आकलन विधि पर आधारित है। यह नवीनतम सर्वेक्षण जुलाई 2009 से जून, 2010 तक अवधि के लिए पूरा हुआ, जिसकी रिपोर्ट 19 मार्च, 2012 को सौंपी गई।

इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में निर्धनता अनुपात व निर्धनों की संख्या की विवरणिका निम्नवत् है—

वर्ष	शहरी क्षेत्रों में			ग्रामीण क्षेत्रों में		
	निरपेक्ष	सापेक्ष	कुल	निरपेक्ष	सापेक्ष	कुल
1993-94	50.1	31.8	45.3	32.86	7.45	40.37
2004-05	41.8	25.7	37.2	32.63	8.08	40.71
2009-10	33.8	20.9	29.8	27.82	7.64	35.47
2011-12	25.7	13.7	21.9	21.65	5.28	26.93

तेन्दुलकर विधि द्वारा दिये गये नवीनतम आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7% तथा सम्पूर्ण देश में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। वर्ष 2011-12 में भारत में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तेन्दुलकर निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं।

निर्धनता अनुपात 2011-12 में

ग्रामीण क्षेत्रों में		शहरी क्षेत्रों में		कुल	
निरपेक्ष	सापेक्ष	निरपेक्ष	सापेक्ष	निरपेक्ष	सापेक्ष
25.70	216.658	13.70	53.125	21.92	269.783

तत्कालीन सरकार और योजना आयोग ने इस तीखी आलोचनाओं से बचने के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन निर्धनता के मापन हेतु विधि की पुनरीक्षा करने के लिए किया। जिसने अपनी रिपोर्ट 2014 में दी। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार संशोधित निर्धनता रेखायें इस प्रकार हैं—

Table 1: Comparison of per capita income in India, 2009-10 and 2011-12

State	2009&10		2011&12	
	Rs. in lakhs	US\$	Rs. in lakhs	US\$
Andhra Pradesh	832.27	1258.09	1031.74	1370.84
Arunachal Pradesh	957.11	1294.03	1151.01	1482.94
Assam	840.87	1232.2	1006.66	1420.12
Bihar	818.77	1032.82	971.28	1229.3
Chhattisgarh	762.55	1167.81	911.8	1229.72
Delhi	975.02	1410.9	1492.46	1538.09
Goa	1025.7	1328.95	1200.6	1470.07
Gujarat	859.35	1244.8	1102.83	1507.06
Haryana	879.65	1275.45	1127.83	1528.31
Himachal Pradesh	827.03	1178.46	1066.6	1411.59
Jammu-Kashmir	847.57	1200.39	1044.48	1403.25
Jharkhand	744.7	1086.07	904.02	1272.06
Karnataka	680.81	1145.52	975.43	1373.28
Kerala	803.06	1139.81	1054.03	1353.68
Madhya Pradesh	772.29	1153.59	941.7	1340.28
Maharashtra	829.29	1331.33	1078.34	1560.38
Madhya Pradesh	923.59	1274.32	1185.19	1561.77
Madhya Pradesh	859.02	1307.2	1110.67	1524.37
Mizoram	981.25	1385.76	1231.03	1703.93
Nagaland	985	1424.22	1229.83	1615.78
Odisha	715.56	1030.67	876.42	1205.37
Punjab	888.08	1230.66	1127.48	1479.27
Rajasthan	864.49	1186.74	1035.97	1406.15
Sikkim	882.49	1302.62	1126.25	1542.67
Tamil Nadu	785.66	1179.8	1081.94	1380.36
Tripura	777.48	1171.57	935.52	1376.55
Uttar Pradesh	768.65	1130.76	889.82	1329.55
Uttarakhand	830.09	1169.82	1014.95	1408.12
West Bengal	767.2	1162.06	934.1	1372.68
West Bengal	557.05	821.03	1130.1	1382.31
India	801	1198	972	1407

Causes of Poverty in India

भारत जैसे विकासशील देश में धन के असमान वितरण के कारण जहाँ एक ओर अमीरी का केन्द्रीयकरण हो रहा है वहीं दूसरी ओर गरीबी का दुष्क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में गरीबी के कुछ प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं—

• Unequal Distribution of Land

भूमि का असमान वितरण भी गरीबी का प्रमुख कारण है क्योंकि भारत में सभी क्षेत्र एक समान गति से विकास नहीं कर रहे हैं। इस प्रमुख कारण प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों (पानी, बिजली, यातायात, संचार, बैंकिंग इत्यादि) का असमान वितरण है जिस कारण रोजगार के अवसरों में क्षेत्रवार विभिन्नता आ जाती है। कई क्षेत्र इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके विकसित हो जाते हैं जबकि अन्य क्षेत्र इन संसाधनों का आभाव में लगातार गरीबी के दुष्क्रम में फंसे रह जाते हैं।

- **f'k{k dk Lrj %Level of Education%**

भारत में आज भी पारम्परिक तरीके से शिक्षा के विकास पर जोर दिया जाता है जबकि लगातार तकनीकी और व्यवहारिक कार्यकुशलताकी माँग में वृद्धि होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता बनी रहती है परन्तु भारत में व्यवहारिक एवं कौशल विकास परख शिक्षा का अभाव पाया जाता है जिस कारण श्रम आधिक्य तो हो जाता है परन्तु उतनी श्रमिक कार्यकुशलता प्राप्त नहीं हो पाती जिस कारण पुनः बेरोजगारी बढ़ने के कारण निर्धनता का स्तर वैसे ही बना रहता है।

- **tul d; k ea of) %Population Growth%**

भारत में जनसंख्या वृद्धि भी गरीबी बढ़ाने का प्रमुख कारण है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आस-पास है जिससे श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती है परन्तु रोजगार के अवसर संसाधनों के अभाव के कारण उतनी वृद्धि प्राप्त नहीं कर पाते और पुनः बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने के कारण गरीबों की श्रेणी में आ जाता है।

- **ikdrd l d k/uka dk vdqky izl/k %Inefficient Management of Natural Resources%**

भारत जैसे विविधता वाले देश में प्राकृतिक संसाधनों का असीम भण्डार उपलब्ध है परन्तु इनके कुशल प्रबन्ध का अभाव गरीबी के बढ़ने का एक मूल कारण है। इनका अकुशल प्रबन्ध पर्याप्त उत्पादन के अभाव का कारण बनता है जिससे कृषि कम होती है। साथ ही नवीन तकनीकों का प्रयोग न होने के कारण इस संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है जिससे गरीबों की संख्या बढ़ती है।

- **dherk ea of) %Increase in Price%**

वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के कारण निर्धन व्यक्ति वस्तुओं को क्रय करने में सक्षम नहीं होता है और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। कीमतों में वृद्धि का देश की निर्धनता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रिजर्व बैंक ने भी स्वीकार किया है, "dher fu; ll=.k ds vfrfjDr xjhch mleyu dk dkbz vksj cf<+ k dk; De ugha gks l drk gA**

- **vkSj kfxdj .k dk vHkko %Lack of Industrialization%**

भारत के उद्योगों में नवीन तकनीकों को तुरन्त अपनाने की अक्षमता एवं उनका अकुशल प्रबन्ध उद्योगों को बन्द होने की कगार पर ले जाता है इससे बेरोजगारी बढ़ती है एवं पुनः निर्धनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- **cjkt xkj h %Unemployment%**

भारत जैसे विकासशील एवं विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए बेरोजगारी एक जटिल समस्या है क्योंकि गरीबी का मूल कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि का होना है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ लोगों का पलायन इस समस्या को और बढ़ा देता है क्योंकि उस अनुपात में रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पाते।

- **xkeh.k xjhch %Rural Poverty%**

ग्रामीण गरीबी से आशय ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी से है। गांवों में आज भी जनता लघु एवं कुटीर उद्योगों पर निर्भर है परन्तु नये अविष्कारों एवं नवीन तकनीकों के प्रयोग के कारण ये उद्योग पिछड़ रहे हैं जिससे पुनः बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो रही है और गरीबी बढ़ रही है।

- **df" k dk fi NMki u %Agriculture Backwardness%**

भारत की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है परन्तु उस अनुपात में उनका राष्ट्रीय आय में योगदान नहीं है। जिसका प्रमुख कारण उन्नत बीजों, सिंचाई की पर्याप्त मात्रा का अभाव एवं नवीन तकनीकों का प्रयोग न होना है। इससे उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो पा रही परिणामस्वरूप गरीबी बढ़ती जा रही है।

• vFk; oLFkk dh /kheh of) nj **Slow Growth of Economy**

विकास की धीमी दर रोजगार में वृद्धि से, आय की अधिकता, उद्योगों के विकास तथा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से बढ़ती है जो कि बेरोजगारी को कम करने के साथ देश में व्याप्त गरीबी को भी कम करती है। विकास की धीमी वृद्धि दर विश्व स्तर पर देश को प्रतिस्पर्धापरक नहीं बना पाती जिससे गरीबी की स्थिति बनी रहती है।

xjhch nj djus ds mi k; **Suggestions for Removing Poverty**

भारत में गरीबी (निर्धनता) को कम करने के लिए ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कौशल, उत्पादन स्तर एवं गति में वृद्धि हो सके। इस सम्बन्ध में किए जाने वाले प्रयत्नों की रूपरेखा इस प्रकार दी जा सकती है—

- नये उद्योगों की स्थापना एवं विद्यमान उद्योगों का विस्तार होने से नये रोजगार के अवसरों का सृजन होगा जिससे बेरोजगारी में कमी आयेगी तथा गरीबी का स्तर कम होगा।
- देश के विकास के लिए कुछ क्षेत्रों में विकसित तकनीकों को लागू करना एवं परम्परागत तकनीकों में सुधार उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं जिससे रोजगार में वृद्धि एवं गरीबी कम होगी।
- शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि करेंगे जिससे नये रोजगार के अवसरों पर वृद्धि होगी एवं गरीबी कम होगी।
- जनसंख्या पर नियन्त्रण व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने एवं रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इससे गरीबी के स्तर में कमी अवश्य आयेगी।
- उत्पत्ति के साधनों का समुचित उपयोग श्रम व प्राकृतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग गरीबी की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- भूमि सुधार तकनीके, उन्नत बीजों एवं तकनीको का प्रयोग कृषि को उन्नति की ओर ले जा सकता है। इससे कृषि आधारित छोटे उद्योगों का विकास एवं भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी की दर में कमी की जा सकती है।
- गरीबी उन्मूलन के विस्तृत राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार सृजन से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम भी व्यक्तियों को रोजगारपरक बनाकर गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Hkkjr es ljdkj }kjk pyk; s tkus okys dN xjhch mlweyu dk; De **Poverty Elimination Programmes run by Government in India**

गरीबी की समस्या को कम करने के लिए भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाये हैं जैसे—राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि।

jkstxkj i nku djus okys dk; De

- ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम
 - स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना—1999
 - सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना—2001
- शहरी क्षेत्र के कार्यक्रम
 - स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना—1997
 - प्रधानमंत्री रोजगार योजना—1993

jk"Vh; | kekftd | gk; rk dk; Øe

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

vU; ; kst uk, j

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन
- उन्नत भारत अभियान-2014
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण-2016
- प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना-2016
- "भारतनेट" योजना-2017
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-2000
- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-1999
- अन्नपूर्णा योजना-2000
- अन्त्योदय अन्न योजना-2000

fu"d"kl

भारत में गरीबी के परिदृश्य में समस्त आंकड़ों को एवं समस्त योजनाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान व्यवस्था में गरीबी को कम करने में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु इसे एक आंदोलन के रूप में लेने की आवश्यकता है, जिसमें आम जनता की जन सहभागिता आवश्यक है, योजनाओं में विशेषकर गरीब परिवारों को स्वयं आगे बढ़कर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा व सरकार को चाहिये कि प्राथमिकता के आधार पर निस्वार्थ भाव से गरीबों का कल्याण करने में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।

| nHkZ xUfK&l ph

- गुरुनानक ग्राम्योद्योग सेवा संस्थान, बरेली, मौलिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण मार्गदर्शिका
- कुरुक्षेत्र पत्रिका, ग्रामीण भारत का बदलता स्वरूप
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सफलता की कहानी
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, "स्वयं सहायता समूह गरीबों का एक राष्ट्रीय अभिमान"
- कुरुक्षेत्र पत्रिका
- व्यावसायिक पर्यावरण

